राजेश पटेल

बनाम

झारखंड राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 1149/2008)

15 मार्च 2013.

[चंद्रमौलि के.आर. प्रसाद और वी. गोपाल गौड़ा, जे.जे.]

दंड संहिता, 1860:

धारा 376 - नीचे की अदालतों द्वारा दोषसिद्धि - आयोजित: तत्काल में मामले में, अभियोजन पक्ष का संस्करण, जैसा कि अभियोजक द्वारा बताया गया है, सबसे अधिक है संभावित और अप्राकृतिक - वह गवाह जिसके बारे में कहा गया है अभियोक्ता को घटना स्थल से बचाया और अभियोक्ता के नियोक्ता ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया मामला - वह डॉक्टर जिसने पीड़िता की चिकित्सीय जांच की और 10 की जांच नहीं की गई - निचली अदालतों ने रोक लगाने में गलती की कि उनकी गैर-परीक्षा से बचाव पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता - इसके अलावा, 11 दिनों की अत्यधिक देरी अभियोजन के लिए घातक है मामला - अभियोक्ता की गवाही अत्यंत अप्राकृतिक है और विश्वास करना असंभव है और इसलिए,

यह प्रेरित नहीं करता है इसे कायम रखने के लिए इसे स्वीकार करने का विश्वास दोषसिद्धि और सजा - अभियोजन मामला बनाया गया है उचित संदेह - इसलिए, संदेह का लाभ अवश्य मिलना चाहिए अपीलार्थी को - आक्षेपित निर्णय निरस्त किया जाता है - भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 136।

अपीलकर्ता पर बलात्कार करने का मुकदमा चलाया गया उसका परिचित और सहपाठी, जो के रूप में काम करता था नर्स। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को धारा 376 के तहत दोषी ठहराया आईपीसी और उसे 7 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उच्च कोर्ट ने दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया

1.1 अभियोजन की कहानी जैसा कि उसके द्वारा बताई गई है अभियोक्ता अत्यंत असंभाव्य और अप्राकृतिक है। अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने के लिए एकमात्र गवाह है। उसके कथन की पुष्टि उसकी मां से की जा रही है पीडब्ल्यू 2 जिसने अभियोजन मामले का समर्थन किया है अभियोक्त्री द्वारा कथित अपराध के वर्णन का आधार यह निर्विवाद तथ्य है कि अपीलकर्ता और दोनों अभियोक्ता सहपाठी थे और अच्छे थे जब वे आदान-प्रदान कर रहे थे तो एक-दूसरे से परिचित हुए पुस्तकें अभियोक्ता ने बताया कि दिनांक 14.2.1993 को वह अपनी किताब लेने के लिए

अपीलकर्ता के घर गई जब वह घर में दाखिल हुई तो उसने दरवाजा बंद कर लिया अंदर जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकी दी चाकू के साथ; इसके बाद अपीलकर्ता ने उसे अंदर बंद कर दिया घर और चला गया; लगभग आधे घंटे के बाद, पीडब्लयू 3, दोनों के एक सामान्य मित्र ने कमरे का ताला खोला। इस दौरान उसने लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अलार्म नहीं बजाया पड़ोसियों। इससे स्पष्टतः पता चलेगा कि अभियोक्ता की गवाही अत्यंत अप्राकृतिक है विश्वास करना असंभव है और यह आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करता है। [पैरा 8] [418-एच; 419-बी-एफ]

1.2 इसके अलावा, लगभग 11 की अत्यधिक देरी हुई है एफआईआर दर्ज करने में कितने दिन द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण अभियोक्त्री का कहना है कि उसने अपने घर जाकर आपबीती बताई घटना उसकी माँ को बताई गई, और पी डब्ल्यू 3 के आश्वासन पर वह मामले में कार्रवाई करेंगे, उनकी मां बनी रहीं 2-4 दिन चुप रहो. में 11 दिनों की अत्यधिक देरी एफआईआर दर्ज करना अभियोजन मामले के लिए घातक है। नीचे की अदालतों द्वारा किए गए निष्कर्ष और टिप्पणियाँ एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी को स्वीकार करते हुए असंतोषजनक कारणों को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि निष्कर्ष और कारण कानून में ग़लत हैं। [पैरा9] [420-बी-सी; 421-बी-सी]

1.3 इसके अलावा, पीडब्लू3, जो का एक सामान्य मित्र है अपीलकर्ता और अभियोक्ता ने कहा कि उन्होंने बचा लिया है उसने घटना स्थल से स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं है. उसके पास है, इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के संस्करण का समर्थन नहीं किया गया। पीडब्लू4 अपने साक्ष्य में कहा है कि अभियोक्ता थी अपने चैंबर में निजी तौर पर नर्सिंग का प्रशिक्षण ले रहे हैं। उसके पास है शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया गया और बी द्वारा जिरह की गई। अभियोग पक्ष में उन्होंने अपनी जिरह की है स्पष्ट रूप से कहा कि उसने पुलिस को बता दिया था कि उसने ऐसा किया था घटना के बारे में कुछ नहीं पता उसके पास और भी है उसने कहा कि न तो अभियोक्ता और न ही उसकी माँ ने उसे बताया घटना के बारे में पी डब्ल्यू3 और पी डब्ल्यू4 के साक्ष्य में अभियोजन मामले को गंभीर रूप से प्रभावित किया। [पैरा 10 और 12] [421-डी-ई, एफ-जी; 422-एफ]

1.4 इसके अलावा, न तो डॉक्टर, जिसके बारे में कहा गया है अभियोजन पक्ष की चिकित्सीय जांच की गई, न ही 1.0। रहा है· अभियोजन डी को साबित करने के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष परीक्षण किया गया मामला। अपीलकर्ता के संज्ञान में लाने में सही था ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ हाई कोर्ट ने भी उक्त दोनों महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ नहीं की है उसके मामले पर पक्षपात किया। इसलिए, खोज और कारण ट्रायल

कोर्ट के साथ-साथ उच्च न्यायालय ई दोनों द्वारा दर्ज किया गया कि डॉक्टर की जांच न होना और 1.0. नहीं है अपीलकर्ता का मामला पूरी तरह से पूर्वाग्रह से ग्रसित है ग़लत दृष्टिकोण. इस कारण से भी, निष्कर्ष और आक्षेपित निर्णय में दर्ज कारण कि ट्रायल कोर्ट का यह मानना उचित था कि अभियोजन अपीलकर्ता और उसके खिलाफ आरोप साबित हो गया है अभियोक्ता पर पूरी तरह से अपराध किया है गलत है और कानून में भी यह पूरी तरह से टिकाऊ नहीं है [पैरा 11-12] [421-एच; 422-ए; 423-ई-ई]

1.5 नीचे की अदालतें, किसी भी स्तर पर, जी नहीं कर सकती थीं कल्पना के आधार पर, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर यह माना गया कि अपीलकर्ता अपराध करने का दोषी है आईपीसी की धारा 376 के तहत दंडनीय। अभियोजन पक्ष का मामला कुछ भी नहीं है प्राकृतिक, न सुसंगत और न ही टिकाऊ होने पर विश्वास करने की संभावना अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा। इसलिए, संदेह का लाभ अपीलकर्ता को मिलना चाहिए। इसके द्वारा आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता है न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, और तदनुसार निर्धारित किया जाता है एक तरफ. [पैरा 12, 15 और 16] [422-एफ-जी; 425-डी-एफ-जी]

राजू बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2008) 5 एससीसी 133 में संदर्भित किया ।

राम कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2006) 9 एससीसी 589 में उद्धृत।

केस कानून संदर्भ:

| | | |
|---|---|---|
| (2006) 9 एससीसी 589 | उद्धृत | पैरा 5 |
| (2008) 5 एससीसी 133 | संदर्भित | पैरा 14 |

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1149/ 2008

झारखंड न्यायालय उच्च आपराधिक अपील संख्या 58/1999 के निर्णय एवं आदेश दिनांक 14.11.2006 से।

संजय हेगड़े, शंकर एन., अरिजीत मजमुदार (एन अन्नपूर्णानी के लिए) अपीलकर्ता के लिए।

अनिल कुमार झा, एस.के. दिवाकर प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय **वी. गोपाल गौड़ा, जे.** द्वारा सुनाया गया

1. यह आपराधिक अपील झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा 1999 की आपराधिक अपील संख्या 58, दिनांक 14.11.2006 में पारित फैसले के

खिलाफ निर्देशित है, जिसमें प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जमशेदपुर द्वारा एस.टी. सं 168 में 1994/172/1995 पारित फैसले और आदेश की पुष्टि की गई है। उक्त निर्णय के द्वारा, अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 376 के तहत दोषी ठहराया गया था और उसे सात साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

2. इस अपील में आग्रह किए गए प्रतिद्वंद्वी कानूनी तर्कों की सराहना करने के उद्देश्य से अभियोजन का मामला संक्षेप में यहां बताया गया है।

3. इस मामले में अभियोजक ने घाटशिला पुलिस स्टेशन में पुलिस के सामने एक बयान दिया है, जिसमें कहा गया है कि उसने अपीलकर्ता के घर में 14.2.1993 को सुबह 11.00 बजे हुई घटना के बारे में बताया है। उसने कहा कि वह पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला के मऊभंडार में डॉ. प्रबीर भगत के नर्सिंग होम में नर्स के रूप में काम कर रही थी। अपीलकर्ता राजेश, जो पीड़िता का सहपाठी प्रतीत होता है, का घर उस नर्सिंग होम के पास स्थित है जिसमें पीड़िता नर्स के रूप में काम कर रही थी। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अपीलकर्ता के अनुरोध पर वह उससे अपनी किताब वापस लेने के लिए उसके घर गई थी। जैसे ही वह अपीलकर्ता के घर में दाखिल हुई, उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उस समय अपीलकर्ता के परिवार के सदस्य घर के अंदर मौजूद नहीं थे। जब पीड़िता ने शोर मचाने की कोशिश की, तो अपीलकर्ता ने उसे आतंकित

कर दिया, जिसने उसे धमकी दी कि अगर उसने शोर मचाया तो उसे चाकू से मार दिया जाएगा। इसके बाद अपीलकर्ता ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जब उसे अपने प्राइवेट पार्ट में दर्द महसूस हुआ तो वह रोना चाहती थी लेकिन अपीलकर्ता ने चाकू दिखाकर उसे चुप करा दिया। बलात्कार का अपराध करने के बाद अपीलकर्ता घर से चला गया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। आधे घंटे के बाद चुंडीह के पूर्णेंदु बाबू आए और घर का ताला खोला और पीड़िता चुपचाप अपने घर लौट गई। अभियोजन पक्ष का यह भी मामला है कि वह अपने घर गई और अपनी मां को घटना के बारे में बताया। हालाँकि, पीड़िता की माँ श्री पूर्णेंदु बाबू के इस आश्वासन पर दो-चार दिनों तक चुप रहीं कि वह मामले में कार्रवाई करेंगे। इसके अतिरिक्त, यह आरोप लगाया गया कि अपराध करने के समय अपीलकर्ता ने पीड़िता को धमकी भी दी थी कि अगर उसने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई तो उसे मार दिया जाएगा।

4. ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया और सात साल की कैद की सजा सुनाई। इसकी सत्यता को विभिन्न कानूनी दलीलों का आग्रह करते हुए 1999 की आपराधिक अपील संख्या 58 दायर करके झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। अपीलकर्ता की ओर से कानूनी दलीलों पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने आरोपी की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की और अपील खारिज कर दी। इस अपील में

इसकी सत्यता को निम्नलिखित कानूनी तर्कों के साथ चुनौती दी गई है: नीचे की अदालतें यह समझने में विफल रही हैं कि अभियोजक की एकमात्र गवाही का इस्तेमाल अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध का दोषी ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता था। अभियोजन पक्ष ने न तो उस डॉक्टर से पूछताछ की है जिसने पीड़िता की मेडिकल जांच की थी और न ही जांच अधिकारी से। इसलिए, इस तथ्य का निष्कर्ष कि अपीलकर्ता अपराध का दोषी है, कानून की दृष्टि से गलत है और खारिज किए जाने योग्य है।अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री संजय हेगड़े द्वारा आग्रह किया गया एक अन्य आधार यह है कि निचली अदालतें इस बात को समझने में विफल रहीं कि अपीलकर्ता के घर में अभियोक्ता को कैद करने की कहानी को कायम नहीं रखा जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पीडब्लू3 पूर्णेंदु बाबू, अपीलकर्ता और अभियोक्ता का एक सामान्य मित्र, जिस पर अभियोक्ता को कथित कारावास से बचाने का आरोप है, ने उसका समर्थन नहीं किया, जिससे अभियोजन की कहानी की घटनाओं की श्रृंखला टूट गई। इसके अलावा, उनका आग्रह है कि निचली अदालतें एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी को नोट करने में विफल रहीं, जिसे पर्याप्त रूप से समझाया नहीं गया है। नीचे दी गई अदालतों ने पीडब्लू 3 और पीडब्लू 4 के हस्तक्षेप के आधार पर एफआईआर दर्ज करने में देरी की व्याख्या की है, अर्थात्, पूर्णेंदु बाबू और नर्सिंग होम के डॉक्टर जिसमें अभियोजन पक्ष काम कर रहा था, क्योंकि उन्होंने पीड़िता को दोनों के बीच

मामले को सुलझाने का आश्वासन दिया था। दलों। हालाँकि, इन दोनों गवाहों को मुकदमे के दौरान या तो अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया या शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया। इसके अलावा, अपीलकर्ता का तर्क है कि निचली अदालतें पीड़िता और उसकी मां के बयान में गंभीर विरोधाभास पर विचार करने में विफल रहीं। अभियोक्ता ने अपनी जिरह में कहा है कि डॉ. प्रबीर भगत - पीडब्लू4 शाम को अपने कक्ष में थे, जब अपीलकर्ता पूर्णेंदु बाबू-पीडब्लू3 के साथ नर्सिंग होम गया था, जबकि अभियोक्ता की मां ने अपनी गवाही में कहा है कि घटना चूंकि डॉक्टर टाटा में थे इसलिए घटना की तारीख पर डॉ. प्रबीर भगत को सूचित नहीं किया जा सका। अपीलकर्ता के अनुसार, नीचे की अदालतों ने अभियोजक के संस्करण में विरोधाभास को नजरअंदाज कर दिया है। एक ओर वह कहती है कि वह 21.2.93 तक अपीलकर्ता से कभी नहीं मिली, दूसरी ओर उसने कहा है कि कथित घटना की शाम, वह डॉ. प्रबीर भगत की डिस्पेंसरी में अपीलकर्ता से मिली थी। अभियोजन पक्ष के स्पष्टीकरण के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया गया कि जब घर बंद था तो वह अलार्म नहीं बजा सकी और उसके साथ अपराध किया जा रहा था क्योंकि अपीलकर्ता ने उसे चाकू से धमकाया था, उसके बयान पर विश्वास करना असंभव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब अपीलकर्ता ने उसके साथ बलात्कार का अपराध किया तो उसने कथित तौर पर अभियोक्ता को आधे घंटे के लिए घर के अंदर बंद कर दिया था, जिससे वह शोर मचा सकती

थी उपरोक्त सभी आधारों के लिए, अपीलकर्ता के वकील का तर्क है कि अपीलकर्ता पर लगाई गई दोषसिद्धि और सजा को कायम रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

5. वैकल्पिक रूप से, विद्वान वकील का तर्क है कि यदि अपीलकर्ता और अभियोजन पक्ष के बीच शारीरिक संबंध स्थापित होता है, तो यह सहमति से यौन संबंध का मामला था। वे दोनों इस तरह के गठबंधन में प्रवेश करने वाले बालिग थे और वे सहपाठी थे और अपराध की कथित घटना से पहले एक-दूसरे से परिचित थे और साथ ही मुलाकात की शर्तों पर भी थे। इसलिए, अपीलकर्ता ने जैसा कि आरोप लगाया गया है, कोई अपराध नहीं किया है। सजा के मुद्दे पर, विद्वान वकील ने राम कुमार बनाम हरियाणा राज्य [1] के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है, क्योंकि वर्तमान मामले में अपीलकर्ता पहले ही 1 वर्ष से अधिक की कैद काट चुका है और अपराध घटित होने की तारीख से 8 महीने और 20 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है और इसलिए उचित आदेश पारित करके अपील की अनुमति दी जा सकती है। अभियोक्ता और अपीलकर्ता दोनों विवाहित हैं और जीवन में व्यवस्थित हैं और अपीलकर्ता कम उम्र का है। इसलिए, यह न्यायालय आईपीसी की धारा 376 के प्रावधानों के तहत दिए गए विशेष और पर्याप्त कारणों को दर्ज करके अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और लगाई गई सजा को अपीलकर्ता द्वारा

न्यायिक हिरासत में पहले से ही बिताई गई अवधि तक कम किया जा सकता है और इसे कारावास और राहत के रूप में माना जा सकता है। यदि अपीलकर्ता की ओर से आग्रह किया गया मामला स्वीकार्य नहीं है, तो उसे इस सीमा तक प्रदान किया जा सकता है जैसा कि राम कुमार मामले (सुप्रा) में देखा गया था।

6. दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पर उच्च न्यायालय और ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों को उचित ठहराने की मांग की। अभियोजन पक्ष के विद्वान वकील का तर्क होगा कि निचली अदालतों ने पीड़िता और उसकी मां की गवाही को स्वीकार करते हुए आरोपी को सही दोषी ठहराया है और सात साल की कैद की सजा सुनाई है और इस अपील में इस अदालत द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए। इसके अलावा, विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता के वकील द्वारा ऊपर उल्लिखित निर्णय वर्तमान मामले की तथ्यों की स्थिति के लिए अनुपयुक्त है और इसलिए, सजा को कम करने के लिए इस अदालत की विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है और इस अपील का बर्खास्तगी के लिए प्रार्थना की जाती है।

7. पार्टियों की ओर से आग्रह की गई उपरोक्त प्रतिद्वंद्वी कानूनी दलीलों के संदर्भ में, हमने यह पता लगाने के लिए मामले की

सावधानीपूर्वक जांच की है कि क्या आक्षेपित निर्णय इस आधार पर इस न्यायालय के हस्तक्षेप की गारंटी देता है कि उच्च न्यायालय द्वारा तथ्य की समवर्ती खोज धारा 376, आईपीसी के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप पर, और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर अपीलकर्ता के खिलाफ इस आरोप पर दर्ज निष्कर्ष कानून में गलत है और यदि हां, तो क्या इसके अभ्यास में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है क्षेत्राधिकार। उक्त बिंदुओं का उत्तर अपीलकर्ता के पक्ष में निम्नलिखित कारण बताते हुए दिया गया है:

8. अभियोजन का मामला यह है कि अपीलकर्ता ने 14.2.1993 को अभियोक्ता पर बलात्कार का अपराध किया था। वह आरोप साबित करने वाली अकेली गवाह है। उसकी मां पीडब्लू2 द्वारा इसकी पुष्टि करने की मांग की गई है, जिसने पीड़िता द्वारा कथित अपराध के बारे में बताए जाने के आधार पर अभियोजन मामले का समर्थन किया है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि अपीलकर्ता और अभियोक्ता दोनों सहपाठी हैं और एक-दूसरे से अच्छी जान-पहचान थी क्योंकि वे पुस्तकों का आदान-प्रदान करते थे। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि उसने अपीलकर्ता को अपनी पुस्तक दी थी। उसने उससे इसे वापस करने के लिए कहा और उसने उसे किताब वापस लेने के लिए 14.2.93 को उसके घर जाने के लिए कहा। तदनुसार, वह अपीलकर्ता के घर गयी। जब वह घर में दाखिल हुई तो उसने घर का

दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उस समय उसने कोई अलार्म नहीं बजाया, सिवाय यह बताने के कि उसने घर का दरवाज़ा बंद न करने पर ज़ोर दिया था क्योंकि उस समय घर में कोई अन्य सदस्य नहीं था। अभियोक्ता का कथन यह है कि वह शोर नहीं मचा सकी क्योंकि अपीलकर्ता ने उसे चाकू से धमकाया था। अभियोजन पक्ष का आगे का मामला यह है कि उसने उसके साथ बलात्कार का अपराध किया था। इसके अलावा उसने कहा कि जब अपीलकर्ता उसके साथ बलात्कार कर रहा था तो उस समय उसके प्राइवेट पार्ट में दर्द हुआ और वह शोर मचाना चाहती थी, लेकिन उसने उसे चाकू दिखाया कि वह शोर न मचाए। इस प्रकार, अभियोक्ता द्वारा बताई गई अभियोजन की कहानी सबसे अविश्वसनीय और अप्राकृतिक है। अपीलकर्ता के इस तर्क को उसकी ओर से आग्रह किए गए तर्क से भी समर्थन मिलता है कि अपराध होने के बाद, अपीलकर्ता ने उसे घर में बंद कर दिया और घर से चली गई। लगभग आधे घंटे के बाद श्री पूर्णेंदु बाबू - पीडब्लू 3, जो अपीलकर्ता और अभियोजक दोनों के एक सामान्य मित्र हैं, वहां आए और कमरे का ताला खोला, तब तक उन्होंने पड़ोसियों का ध्यान आकर्षित करते हुए अलार्म नहीं बजाया। उपरोक्त परिस्थिति से यह स्पष्ट होता है कि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि अभियोजन का मामला स्वाभाविक एवं संभावित नहीं है। न तो अभियोक्ता ने और न ही पीडब्लू3 ने पुलिस को उस कथित अपराध के संबंध में सूचित किया है जो अभियोक्ता द्वारा घर से बाहर निकलने के बाद किया गया था। अभियोजन पक्ष द्वारा दिया गया

कारण यह है कि पी डब्ल्यू 3 अपीलकर्ता और अभियोक्ता के बीच विवाह का समझौता कराने के लिए ईमानदार प्रयास कर रहा था। ऐसा नहीं हुआ और इसलिए, 25.2.93 को क्षेत्राधिकार पुलिस के पास शिकायत दर्ज की गई। उसके और अपीलकर्ता के बीच समझौते के संबंध में पी डब्ल्यू 1 का उपरोक्त संस्करण साबित नहीं हुआ है क्योंकि पी डब्ल्यू 3 ने अपने साक्ष्य में कहा है कि वह कथित अपराध के संबंध में कुछ भी नहीं जानता है।

9. इसके अलावा, क्षेत्राधिकार पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करने में लगभग 11 दिनों की अत्यधिक देरी हुई है। अपीलकर्ता द्वारा किए गए कथित अपराध के बाद उचित अवधि के भीतर शिकायत दर्ज न करने पर अभियोजक द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण यह है कि वह अपने घर गई और अपीलकर्ता द्वारा किए गए अपराध के बारे में अपनी मां को बताया और पूर्णेंदु बाबू के आश्वासन पर - पीडब्लू 3, मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन देकर मां दो-चार दिन तक चुप रही। इसके अलावा, देरी के संबंध में अभियोजक द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण यह है कि अपराध के समय अपीलकर्ता ने उसे धमकी दी थी कि यदि वह उसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराती है, तो उसे मार दिया जाएगा। उक्त स्पष्टीकरण एक बार फिर तर्कसंगत स्पष्टीकरण नहीं है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने तुरंत या उचित अवधि के भीतर शिकायत दर्ज न करने के संबंध में जो कारण बताया, उसमें यह पाया गया कि बलात्कार के मामले में, पीड़ित लड़की

शायद ही पुलिस स्टेशन जाने और मामले को सबके सामने लाने की हिम्मत कर पाती है। बदनामी का डर जो उन लड़कियों के साथ जुड़ा होगा जिनका बलात्कार किया गया है। साथ ही, ट्रायल कोर्ट द्वारा बताए गए कारण जो अपीलकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने में देरी के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए स्पष्टीकरण को उचित ठहराते हैं, को उच्च न्यायालय ने आक्षेपित फैसले में गलती से स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा, देरी के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा आगे की गई टिप्पणी यह है कि पीड़िता और उसकी मां ने पीडब्लू 3, जो उन दोनों का एक सामान्य मित्र है और पीडब्लू 4, वह डॉक्टर जिसके साथ पीड़िता थी, के हस्तक्षेप से न्याय पाने की कोशिश की। अभियोक्त्री नर्स के पद पर कार्यरत थी। जब ऐसा नहीं हुआ, तो 11 दिन बीत जाने के बाद, अपीलकर्ता द्वारा किए गए अपराध के लिए क्षेत्राधिकार पुलिस के पास एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने यह कारण भी दर्ज करना शुरू कर दिया है कि अभियोजक के पास 14.2.93 के बजाय घटना की अलग तारीख देने का पूरा अवसर था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जो कारण कानून में मान्य नहीं है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने विद्वान ट्रायल न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणी को स्वीकार कर लिया, जिसमें पुलिस को मामले की रिपोर्ट करने के मामले में अपीलकर्ता द्वारा मारे जाने के लिए आतंकित किए जाने के बारे में अभियोजन पक्ष ने अपने साक्ष्य में जो स्पष्टीकरण दिया था, वह कानून में पूरी तरह से अक्षम्य है। यह न केवल

अप्राकृतिक है बल्कि असंभाव्य भी है। इसलिए, अपीलकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में 11 दिनों की अत्यधिक देरी अभियोजन मामले के लिए घातक है। एफआईआर दर्ज करने में अत्यधिक देरी के संबंध में यह महत्वपूर्ण पहलू न केवल अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार करना असंभव बनाता है, बल्कि ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों में दिए गए कारण और टिप्पणियाँ कानून में पूरी तरह से अस्थिर हैं और इसलिए, उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

10. इसके अलावा, मौजूदा मामले में, पीडब्लू 3, जो अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार अपीलकर्ता और अभियोजक का एक सामान्य मित्र है, उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह उस मामले के बारे में कुछ भी नहीं जानता जिसके लिए उसे नोटिस मिला था। अदालत को मामले में गवाही देनी है। पीडब्लू4 ने अपने साक्ष्य में कहा है कि अभियोक्ता अपनी परीक्षा की तारीख, अर्थात् 16.11.95 को पिछले तीन वर्षों से अपने कक्ष में निजी तौर पर नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थी। उन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि 14.2.93 को जब उन्होंने अपना कक्ष खोला तो अभियोक्ता उनके कक्ष में आई और आगे कहा कि उसकी माँ ने उसे कुछ नहीं बताया। अभियोजन पक्ष ने उसके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया है, अभियोजक द्वारा उससे जिरह की गई, अपनी जिरह में उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने पुलिस को बताया है कि वह घटना के बारे में कुछ भी नहीं जानता

है। उन्होंने आगे कहा है कि न तो पीड़िता और न ही उसकी मां ने उन्हें घटना के बारे में बताया और आगे कहा कि उन्हें मामले के बारे में कुछ भी नहीं पता है।

11. इसके अलावा, अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष न तो डॉक्टर और न ही आईओ से पूछताछ की गई है। अपीलकर्ता ने ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ उच्च न्यायालय के ध्यान में यह बात लाने में सही था कि मामले में उपरोक्त दो महत्वपूर्ण गवाहों की गैर-परीक्षा ने अपीलकर्ता के मामले पर इस कारण से प्रतिकूल प्रभाव डाला है कि यदि डॉक्टर को जांच की गई कि वह पीड़िता के गुप्तांग या उसके शरीर के किसी अन्य हिस्से पर चोट लगने और हाइमन परत की प्रकृति आदि के बारे में साक्ष्य प्राप्त कर सकता था, ताकि अभियोजन की कहानी की पुष्टि हो सके कि पीड़िता को असहनीय दर्द का सामना करना पड़ा था। अपीलकर्ता ने उसके साथ बलात्कार किया। घटना के 12 दिनों के बाद उसकी जांच करने वाले डॉक्टर की जांच न करने से बचाव पक्ष के मामले पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि अपीलकर्ता द्वारा किए गए कथित अपराध के 12 दिनों के बाद पीड़िता की जांच की गई थी क्योंकि उस समय तक बलात्कार का निशान गायब हो गया होगा. भले ही यह मान लिया गया हो कि पीड़िता का हाइमन फटा हुआ पाया गया था और उसके प्राइवेट पार्ट या उसके शरीर के किसी अन्य हिस्से पर कोई चोट

नहीं पाई गई थी, हाइमन के ऐसे टूटने का पता लगाना वर्तमान उम्र में कई कारणों से हो सकता है जब पीड़िता की मृत्यु हो गई थी। एक कामकाजी लड़की और वह अपने घर की चारदीवारी के अंदर बेकार जीवन नहीं जी रही थी। उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया उक्त तर्क कानून की दृष्टि से पूरी तरह से गलत है।

12. पीडब्लू 3 और पीडब्लू 4 के साक्ष्यों के उपरोक्त बयान के मद्देनजर, जिनके साक्ष्य अभियोजन पक्ष के लिए अपने मामले के अनुसार घटनाओं की श्रृंखला को साबित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, उपरोक्त गवाहों के साक्ष्यों के बयान ने अभियोजन मामले को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इसलिए, निचली अदालतें किसी भी हद तक, रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर यह नहीं मान सकती थीं कि अपीलकर्ता आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध करने का दोषी है। इसके अलावा, अभियोक्ता के अनुसार, पी डब्ल्यू 3, जिस पर आरोप है कि उसने उसे अपराध की जगह से बचाया था, ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि वह अपने बयान में घटना के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, इसलिए वह अभियोजन पक्ष के संस्करण का समर्थन नहीं करता है। उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के इस निष्कर्ष को गलती से स्वीकार कर लिया है कि अपीलकर्ता को डॉक्टर की गैर-परीक्षा के कारण पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं किया गया है क्योंकि वह पीडब्ल्यू 4 के निजी अस्पताल में एक नर्स के रूप में काम कर रही थी

और एक नर्स होने के नाते वह जानती थी कि बलात्कार की सूचना गंभीर प्रकृति की है और यदि घटना सच होती तो वह पुलिस को सूचना देने में नहीं हिचकिचाती। इसके अलावा, निचली अदालतों का निष्कर्ष है कि इस मामले में जांच करने वाले अभियोजन पक्ष द्वारा आईओ से पूछताछ न करने से अपीलकर्ता के मामले पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि अभियोजन पक्ष के गवाह अभियोजन पक्ष के प्रतिकूल थे, जिनसे या तो पूछताछ की गई थी। या अभियोजन पक्ष द्वारा शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया, जो तर्क कानून में पूरी तरह से अस्थिर है। इसलिए, मामले में उपरोक्त दो गवाहों की गैर-परीक्षा के संबंध में ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष और कारणों ने अपीलकर्ता के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला है, यह पूरी तरह से नीचे की अदालतों का एक गलत दृष्टिकोण है। इस कारण से भी, हमें यह मानना होगा कि आक्षेपित निर्णय में दर्ज निष्कर्ष और कारण कि ट्रायल कोर्ट का यह मानना उचित था कि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप साबित कर दिया है और उसने अभियोजक पर अपराध किया है, पूरी तरह से सही है। गलत है और कानून में भी यह पूरी तरह से टिकाऊ नहीं है।

13. ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज अपीलकर्ता की सजा के संबंध में निष्कर्ष, जिसे उच्च न्यायालय ने अभियोक्ता की एकान्त गवाही के आधार पर

स्वीकार कर लिया है, जो उसकी मां पीडब्लू 2 के साक्ष्य द्वारा समर्थित है, एक बार फिर एक गलत दृष्टिकोण है। उच्च न्यायालय का भाग. अपीलकर्ता द्वारा किया गया कथित बलात्कार का अपराध बिना किसी सबूत के स्थापित हो गया क्योंकि अभियोजन पक्ष पीड़िता द्वारा बताई गई घटनाओं की श्रृंखला को साबित करने में विफल रहा। चूँकि पी डब्ल्यू3 और पी डब्ल्यू 4 के साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करते थे, लेकिन दूसरी ओर, उनके साक्ष्य ने अभियोजन की कहानी को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इसलिए, निचली अदालतें अपीलकर्ता को आरोप के लिए दोषी नहीं मान सकती थीं और उसे बलात्कार के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहरा सकती थीं और सजा नहीं दे सकती थीं।

14. इसके अलावा, एक और मजबूत परिस्थिति जो हमारे दिमाग में है वह यह है कि वे एक-दूसरे से अच्छे परिचित थे क्योंकि वे सहपाठी थे और उनका एक-दूसरे से मिलना-जुलना भी था। बचाव पक्ष के वकील ने वैकल्पिक रूप से तर्क दिया था कि अपीलकर्ता ने अपनी सहमति से यौन संबंध बनाए थे। उच्च न्यायालय ने यह तर्क देते हुए उक्त तर्क को स्वीकार नहीं किया कि अपीलकर्ता यह समझाने में विफल रहा कि किस परिस्थिति में उसने पीड़िता की सहमति से यौन संबंध बनाया जब वह उसके घर में कैद थी। अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि यह अभियोक्ता के साथ सहमति से यौन संबंध था, इस कारण से माना जा सकता है कि वह

स्वयं अपीलकर्ता के घर गई थी, हालांकि उसका कहना है कि वह अपीलकर्ता के अनुरोध पर वापस लेने के लिए वहां गई थी। उसकी किताब जो उसने उसे दी थी। यह इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एक मजबूत परिस्थिति है कि अपीलकर्ता का बचाव मामला सहमति से किया गया यौन संबंध है। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अपीलकर्ता द्वारा अपराध करने के बाद उसने कमरे को बाहर से बंद कर दिया था और चला गया था। आधे घंटे के बाद पूर्णेन्दु बाबू-पीडब्ल्यू3 पहुंचे और कमरे का ताला खोला। इस कहानी पर विश्वास करना असंभव है और अभियोजक ने घटना की तारीख से तुरंत या उचित अवधि के भीतर शिकायत दर्ज नहीं की है। अभियोजन पक्ष द्वारा 11 दिन बीत जाने के बाद निर्विवाद रूप से शिकायत दर्ज की गई थी। इस संबंध में, राजू बनाम मध्य प्रदेश राज्य [2] में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करना उचित है , जिसका प्रासंगिक पैराग्राफ हमारे निष्कर्ष के समर्थन में बेहतर सराहना के लिए यहां निकाला गया है:

> "12. गुरमीत सिंह मामले में 1983 में दंड संहिता की धारा 375 और 376 में संशोधन का संदर्भ दिया गया है, जिससे बलात्कार से संबंधित दंडात्मक प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाया गया है, और साक्ष्य अधिनियम की धारा 114-ए के संबंध में भी अनुमान लगाया गया है। कथित बलात्कार के एक मामले में

सहमति से यौन संबंध बनाने के आरोपों के संबंध में उठाया गया। हालाँकि यह महत्वपूर्ण है कि धारा 113-ए और 113-बी को भी उसी संशोधन द्वारा साक्ष्य अधिनियम में शामिल किया गया था, जिसके द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने और दहेज हत्या के मामलों में आरोपियों के खिलाफ कुछ अनुमान लगाए गए हैं। इस प्रकार, ये दो धाराएं अभियोजन पक्ष के पक्ष में एक स्पष्ट अनुमान लगाती हैं लेकिन बलात्कार के संबंध में कोई समान अनुमान नहीं लगाया गया है क्योंकि धारा 114-ए के तहत अनुमान इसकी प्रयोज्यता में बेहद प्रतिबंधित है। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जहां तक बलात्कार के आरोपों का सवाल है, पीड़िता के साक्ष्य की जांच एक घायल गवाह के रूप में की जानी चाहिए, जिसकी घटनास्थल पर उपस्थिति संभावित है, लेकिन यह कभी नहीं माना जा सकता है कि उसके बयान को, बिना किसी अपवाद के, के रूप में लिया जाना चाहिए। सुसमाचार सत्य. इसके अतिरिक्त, उसके बयान को, अधिक से अधिक, इस सिद्धांत पर आंका जा सकता है कि आमतौर पर कोई भी घायल गवाह झूठ नहीं बोलेगा या किसी व्यक्ति को झूठा नहीं फंसाएगा। हमारा मानना है कि इन सिद्धांतों के तहत ही इस मामले और इस जैसे अन्य मामलों की जांच की जानी चाहिए।"

15. उपरोक्त कारणों से अभियोजन का मामला अपीलकर्ता द्वारा किए गए कथित अपराध के लिए उसकी दोषसिद्धि और सजा को बनाए रखने के लिए स्वाभाविक, सुसंगत और संभावित नहीं है।

16. ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ उच्च न्यायालय को देरी के संबंध में रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की सराहना करनी चाहिए थी और अभियोजन पक्ष द्वारा एफआईआर दर्ज करने में 11 दिनों की देरी और शिकायतकर्ता गवाहों की गैर-परीक्षा के संबंध में उचित स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए था। डॉक्टर और आईओ ने न केवल अपीलकर्ता के मामले पर बल्कि अभियोजन के मामले पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जिससे इस न्यायालय के मन में उचित संदेह पैदा हुआ है। इसलिए, संदेह का लाभ अपीलकर्ता को मिलना चाहिए। जैसा कि हमने ऊपर कहा है कि अभियोक्ता की गवाही पर विश्वास करना सबसे अप्राकृतिक और असंभव है और इसलिए यह दोषसिद्धि और सजा को बनाए रखने के लिए इसे स्वीकार करने के लिए आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करता है। इसलिए, हमारा विचार है कि इस न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। तदनुसार, हम अपील की अनुमति देते हैं और आक्षेपित निर्णय को रद्द कर देते हैं।

17. यदि अपीलकर्ता ने जमानत बांड निष्पादित कर दिया है, तो उसे उन्मोचित किया जा सकता है।

आर. पी. अपील स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टुल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी कामाक्षी मीना (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अग्रेंजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अग्रेंजी संस्करण ही मान्य होगा।